

संपादकीय

न्याय के हक में

एक बड़ी गलती को सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा पाए ग्यारह दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों के दौरान गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक दुराचार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इन जघन्य अपराधों के लिये ग्यारह लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। जिन्हें वर्ष 2022 में चौदह साल की सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया गया था। दरअसल, गुजरात सरकार ने उम्रकैद की सजा के मामले में अपराधियों को छूट देने वाली 1992 की नीति के आधार पर यह रिहाई की थी, जबकि वर्ष 2014 में नई नीति ने जघन्य अपराधियों की रिहाई पर रोक लगाई थी। यहीं वजह है कि कोर्ट ने भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून के शासन का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई देने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि निष्पक्ष न्याय के लिये इस मामले में महाराष्ट्र में मुकदमा चला और सजा सुनाई गई। ऐसे में केवल महाराष्ट्र सरकार ही दोषियों की रिहाई का फैसला ले सकती थी। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काटने वाले ग्यारह लोगों को दो सप्ताह में जेल वापस जाने को कहा है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत का फैसला गुजरात सरकार की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। दरअसल, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी थी कि सजा पाने वाले लोगों ने जेल में 14 साल पूरे कर लिये थे, उनका आचरण अच्छा पाया गया तथा केंद्र सरकार ने समयपूर्व रिहाई के संबंध में सहमति दी थी। हालांकि, सीबीआई ने तकर किया था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के साथ कोई रियाध की जिम्मेदारी नहीं है।

नहीं बरती जानी चाहए। लोकेन इसके बावजूद उन्हें रिहा कर दिया गया था। इतना ही नहीं, गोधरा उप-जेल से बाहर निकलने के बाद दोषियों का माला पहनाकर अभिनंदन तक किया गया था। दरअसल, उम्रक्रैंड की सजा पाए लोगों को समय से पहले रिहा करने के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आखिरकार उसे न्याय मिला, बल्कि इससे खुद सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा फिर स्थापित हुई। समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ न्याय की उम्मीद से लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। निस्संदेह, इस मामले में गठित खंडपीठ ने सही मायनों में कानून के शासन को ही प्रतिष्ठा दी है। उसने शीर्ष अदालत के मई, 2022 में दिये गए फैसले को भी पलटा है, जिसमें गुजरात सरकार के छूट देने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। यह सामान्य विवेक की बात है कि तमाम दलीलों के बावजूद सामूहिक बलात्कार व हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों को समय से पहले रिहाई नहीं दी जानी चाहिए। रिहाई के फैसले ने राज्य सरकार के कल्याणकारी स्वरूप व निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। आरोप है कि राज्य सरकार ने जेल में रहने के दौरान भी दोषियों को लंबे-लंबे समय के लिये पेरोल पर बाहर आने की इजाजत दी थी। दरअसल, ऐसे मामलों में राज्य सरकार के विवेक की भी परीक्षा होती है कि उसके किसी निर्णय से पीड़ित पक्ष आहत न हो। सही मायनों में न्याय की प्रकृति का भी सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को उन भयावह स्थितियों व पीड़िता की पीड़ा का भी अहसास होना चाहिए। यह राज्य सरकार की कल्याणकारी रीतियों-नीतियों की भी परीक्षा थी। वहीं कोर्ट ने अदालत को गुमराह करने और गलत तथ्य पेश करने का आरोप भी राज्य सरकार पर लगाया। बहरहाल, अब दोषी दो हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करेंगे और पूरी सजा होने तक जेल में ही रहेंगे। निस्संदेह, शीर्ष अदालत के फैसले से जहां रिहाई के अधिकार के प्रश्न का जवाब मिला, वहीं पीड़िता को न्याय पाने के हक की भी पुष्टि हुई। पीड़िता के अधिकार को महत्वपूर्ण मानने से सही मायनों में उसे न्याय मिल पाया। बहरहाल, देश में कानून के राज को प्रतिष्ठा देकर न्यायालय ने एक आदर्श मार्गदर्शक की भूमिका का भी निर्वहन किया है।

ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुहम्मद ने लगा नहीं!

नीरज कुमार दुबे

मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जु सिर्फ भारत विरोधी नहीं हैं बल्कि उनके इतिहास पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि वह किसी के साथ नहीं हैं। हम आपको बता दें कि मोहम्मद मुइज्जु ने चीन समर्थक माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की उंगली पकड़ कर राजनीति में कदम रखा, उनके नवशैक्षणिक पर चलते हुए भारत विरोध को हवा दी और आखिरकार राष्ट्रपति पद तक पहुंच गये। लेकिन अब माना जा रहा है कि मुइज्जु के संबंध अपने गुरु अब्दुल्ला यामीन के साथ बिंगड़ गये हैं। हालात ऐसे हो गये हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा काट रहे अब्दुल्ला यामीन अपने ही घोले मुइज्जु और अपनी ही पार्टी का विरोध नई पार्टी बनाकर कर सकते हैं। यामीन को उमीद थी कि उनकी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने पर उह्ये रिहा करवाने का प्रयास किया जायेगा लेकिन मुइज्जु ने सत्ता पर पूरी तरह अपनी पकड़ कायम करने के लिए यामीन को दरकिनार कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद संभालने वाले दिन मदज्ज़ ने उन लोगों की ओर देखा तक नहीं जिन्होंने राजनीति

में आगे बढ़ने में उनकी मदद की थी। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला यामीन शुरू से ही मुझ्जू के इस स्वार्थी रुख से वाकिफ़ थे इसलिए वह उन्हें अभी राष्ट्रपति चुनाव का टिकट भी नहीं दिलवाना चाहते थे। लेकिन अपनी उम्मीदवारी के लिए पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को मनाने में मुझ्जू का मायाब रहे थे। बताया जाता है कि जेल की सजा के कारण मोहम्मद यामीन के पास मुझ्जू की उम्मीदवारी का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था इसलिए उन्होंने मजबूत होकर अपनी पत्नी के माध्यम से अपनी सहमति पार्टी के पास उस दिन भेजी जबकि मुझ्जू चुनाव आयोग के समर्थन अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुझ्जू की जीत के जशन के दौरान और उसके बाद घटनाओं से पूर्व राष्ट्रपति यामीन और उनके साथी डॉ. मोहम्मद जमील अहमद के मन में नाराजगी स्पष्ट हो गयी थी क्योंकि लगातार उनका अपमान किया जा रहा था। हम आपको यह भी बता दें कि मालदीव में 30 सितंबर को हुए चुनावों के बाद और मतगणना के बीच ही जमील और उनके सदस्योंगये ने जनता को आगाह करना शुरू कर दिया था कि उन्हें आने वाली

सरकार के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह से देखा जाये तो नई सरकार के औपचारिक रूप से सत्ता संभालने से पहले ही मालदीव में असंतोष का माहौल शुरू हो गया था। मालदीव के चैनल 13 पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉ. मोहम्मद जमील अहमद ने कहा कि यामीन चाहते थे कि वह राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डॉ. मुझ्जून के जश्न में भाग लें। जमील के अनुसार, यामीन ने डॉ. मुझ्जून से यह भी अनुरोध किया था कि जब तब वह पूरी तरह से रिहा नहीं हो जाते, तब तक जश्न का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए। जमील ने कहा कि अगर मुझ्जून चाहते तो तत्कालीन सरकार यामीन को उनकी आपाधिक सजा के बावजूद जश्न में भाग लेने की अनुमति देती। जमील के अनुसार मुझ्जून ने अपने विजयी संवोधन में भी यामीन के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया था। हम आपको बता दें कि यामीन के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉ. जमील उपराष्ट्रपति थे। हालांकि उनको बाद में पद से हटा दिया गया था। उपराष्ट्रपति पद से बर्खास्त होने के बाद जमील ने यामीन के खिलाफ लंबे समय तक हमला बोला था और 2018 में यामीन को सत्ता से हटाने के लिए मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की राजनीतिक गतिविधियों के पीछे उन्हीं का हाथ माना जाता है। लेकिन अपने रुख में पूर्ण बदलाव के बाद जमील अब यामीन के प्रमुख पक्षकार बन गये हैं और एप्रिल नेशनल फँट (पीएनएफ) नामक नई राजनीतीक पार्टी बनाने के प्रयासों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। चुनावी जीत के जश्न के कार्यक्रम में यामीन की उपस्थिति की अनुमति देने में डॉ. मुझ्जून की ओर से दिखायी गयी उपेक्षा के बारे में जमील ने कहा, “वेशक हमें उम्मीद थी कि वे इस दोस्ती और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का सम्मान करना जारी रखेंगे। यामीन भी इसके उतने ही कदमदार हैं। समारोह के दौरान उहँ हृजित श्रेय और धन्यवाद मिलना चाहिए था। लेकिन हमने इस संबंध में कुछ भी नहीं सुना और इस बात ने तुरंत भावनात्मक रूप से हम पर गहरा प्रभाव डाला। यह भी बताया जाता है कि चुनाव में जीत के बाद मुझ्जून ने जब विजयी संवोधन दिया तो उसके दीक बाद उहँ यामीन का फोन आया। लेकिन मुझ्जून ने कॉल का जवाब देने से ही इकार कर दिया। यहीं नहीं, मुझ्जून ने यामीन के इकॉल मी बैंक के संदेशों को भी नज़रअंदाज कर दिया।

भारत के ऋण को नियंत्रित करने की आवश्यकता

भारत के वर्तमान सामान्य सरकारी ऋण के बारे में तुरंत घबराहट की आवश्यकता नहीं है, परन्तु अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोड की चेतावनी कि यह मध्यम अवधि 1 में या 2028 तक देश के सकल धरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 100 प्रतिशत से अधिक हो सकता है चिंता का विषय है। आईएमएफ ने कहा है कि दीर्घकालिक जीवित अधिक हों और उसने शिवितोषण के नये और अधिमानतर्स रियायती ज्ञातों की आवश्यकता पर भी भी जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि आईएमएफ का भारत के कार्यकारी निदेशक, के वी सुधमण्डन ने कहा संभव ऋण से जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि यह मुख्य रूप से धरेलू मुद्रा में दर्शाया गया है। पिछले दो दशकों में वैशिक अर्थवद्यरण का सामना करने वाले झटकों की भीड़ के बावजूद, भारत का सार्वजनिक ऋण—से—जीडीपी अनुपात 2005–06 में 81 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 84 प्रतिशत हो गया था जो 2022–23 में पुनरु 81 प्रतिशत हो गया। आईएमएफ ने 2023 में वैशिक ऋण के + 97 खरब होने का आकलन किया है। आईएमएफ ने कहा कि भारत को अपने सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए मध्यम अवधि में महत्वाकांक्षी राजकोषीय समेकन की आवश्यकता है। इसने कहाँस्तिक अवधि में एक तेज

वैशिक विकास की मंदी व्यापार और वित्तीय चौनलों के माध्यम से भारत को प्रभावित करेगी। आगे वैशिक आपूर्ति व्यवधानों से आवर्तक वस्तु मूल्य अस्थिरता हो सकती है, जिससे भारत के लिए राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है। घेरेलू रूप से, मौसम के झटके मुद्रास्फीति के दबाव को प्रज्ञलित कर सकते हैं और आगे खाद्य निर्यात प्रतिवेंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि स्थितियां बहुत अच्छी हुई तो इसके विपरीत अपेक्षित उपभोक्ता मांग और निजी निवेश को बढ़ावा दे सकता है।¹ आईएमएफ अपने बयान के अंतिम भाग के बारे में बिल्कुल सही है कि भारत में उत्पादन वढ़ती उपभोक्ता मांग उच्च उत्पादन, आपूर्ति और निवेश को प्रेरित कर रही है। भारत की आयात—नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था मौजूदा वैशिक मंदी के खिलाफ कुछ हद तक अछूता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़कर, अर्थव्यवस्था को अगले 10 वर्षों में कम से कम तेज गति से बढ़ने की उमीद है। पिछले हफ्ते यह बताया गया कि दुनिया भर की सरकारों द्वारा संचित समग्र सार्वजनिक ऋण 2023 में + 97 ट्रिलियन पर था। यह 2019 में जो कुछ भी था, उससे 40प्रतिशत अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल विश्व सार्वजनिक ऋण का 33प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका का ऋण—जीडीपी अनुपात प्रतिशत है। जापान के यह 255.2प्रतिशत है, जो वैशिक ऋण का 11प्रतिशत है।² भारत का 143.7प्रतिशत है, और विश्व बाद फ्रांस (101प्रतिशत), वियतनाम (106.4प्रतिशत), यूके (106.4प्रतिशत), ब्राजील (88.1प्रतिशत) और चीन (83प्रतिशत) है।³ एक दशक में कुल वैशिक मौजूदा + 100ट्रिलियन की वृद्धि है, जो सरकारों, घरों और बेत्र द्वारा ऋण संचय की तरफ को एक साथ दिखाती है। की पहली छमाही में दुनिया जीडीपी के 336प्रतिशत के कुल वैशिक ऋण + 100ट्रिलियन का लेखांकन था के लिए, भारत सरकार की विधियां निवित्त रूप से अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ वित्ताजनक नहीं है। हालांकि कई राज्यों की ऋण स्थिति बारे में भी ऐसा नहीं कह सकता है, जो सीमित रूप सूजन क्षमताओं का सामना रह है, जिससे बड़े पैमाने पर य सेवा समर्पयां होती हैं। को हर साल अधिक उधार के लिए मजबूर होना पड़ जाता है, जो उनके ऋण का बोझ जारी है। पंजाब के 2023–24 में अनुमानित ऋण—राज्य जीडीपी अनुपात 8प्रतिशत है। इसके बाद हैं (37.8प्रतिशत), परिवहन बंगाल 7प्रतिशत), राजस्थान

3.3 नए, वक्तव्य के लिए उत्तर प्रदेश (33.4प्रतिशत), अन्ध्र प्रदेश (36.6प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (32.1प्रतिशत), मध्य प्रदेश (30.4प्रतिशत), तमिलनाडु (25.6प्रतिशत) और असम (24.4प्रतिशत)। कुछ छोटे भारतीय राज्यों में बहुत अधिक ऋण—एसजीडीपी अनुपात है। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश में अनुपात 53प्रतिशत है। उच्च ऋण—एसजीडीपी अनुपात वाले राज्यों में पंजाब, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। राज्य सरकार के ऋण में उनके समग्र उदाहरण का 65 अप्रतिशत शामिल है। वे अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच 28प्रतिशत बढ़े। आर्थिक तिथि 1 में मंदी के कारण एसजीडीपी विकास को नकारात्मक जोखिम हो सकता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के बढ़ते ऋण रखते एक विकासशील संघीय अर्थव्यवस्था में स्वामानिक लगेंगे। दुर्भाग्य से, इन सरकारी ऋणों के पीछे के कारण विकास की तुलना में निःशुल्क सेवा एवं धन देने के साथ अधिक जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए एक आंख के साथ कम आय वाले समझौतों को बड़े पैमाने पर निःशुल्क सेवा और नकद दे रही हैं। उदाहरण के लिए, प्रदानमंत्री नंदेंग मोदी ने पिछले साल नवंबर में घोषणा की थी कि राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों के लिए सरकार की मुफ्त खाद्य अनाज योजनाओं लाख साल के लिए बढ़ायी जायेगी जिससे 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसमें 11 लाख करोड़ खर्च होगा। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार के अपने अनुमान से, देश में गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। जाहिर है, राशन की दुकानों के माध्यम से भोजन का उपहार राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव के मद्देनजर दिया गया है। राज्य सरकारों के शीर्ष पर राजनीतीक दल एक—दूसरे के साथ उपहार देने में प्रतिरक्षण पर रहे हैं, जबकि भारत के अधिकांश सेवानिवृत्त औद्योगिक कर्मचारियों को केवल 10 रुपये का योगदान पेशन के रूप में प्रति माह दिया जाता है। देश और राज्यों के लिए एक उच्च ऋण—जीडीपी अनुपात का स्वागत किया जा सकता है यदि यह सामाजिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के सुधार पर उच्च विकास व्यय का परिणाम है। परन्तु वर्तमान ऋण में वृद्धि इसके कारण नहीं है। यह तो उपहारों के कारण है। यह मूलरूप से उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के लिए वोट हासिल करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों में, गरीब शासन की गुणवत्ता जिम्मेदार ऋण प्रबंधन को प्रभावित कर रही है।

ईसाई समुदाय को लुभाने में जुटे मोदी

राम पुनियानी

गत 25 दिसंबर, 2023 को धानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई साईयों को फिसमस की बधाई दी ने और उनसे बातचीत करने के लिए अपने घर निम्नित कैफा। उहोंने समाजसेवा के लिए गोपदान और प्रभु इसा मरीह की समावेशी शिक्षाओं की सराहना की। उहोंने इसाई समुदाय के लोगों से अपने पुणे और लम्बे बांदों के बारे में भी अपने मेहमानों ने बताया। इसके कुछ दिन बाद केरल में कुछ सैकड़ा साईयों ने भाजपा की सदस्यता ली। द हिन्दू ने लिखा भाजपा की राज्य इकाई की कोट्यम भैं ई बैठक में तय किया गया कि इसाई समुदाय को आकर्षित करने के लिए 10 दिन की छह यात्रा निकाली जाएगी जेसके दौरान पार्टी मणिपुर हिस्से के लिहित विभिन्न समूहों पर अपनी विश्वासीता त समुदाय के सामने रखेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिण्यारी विजयन ने बिलवल ठीक कहा कि मणिपुर में हालत यह हो ई है कि आबादी का एक दोस्त... इसाई समुदाय वहाँ ही नहीं सकता... हम सबने खा है कि इस मामले में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने चुप्पी बरपा रखी है (द झाइयन एक्सप्रेस, बईं, जनवरी 2 2024)। अगला दाम चुनाव नजदीक है और गणराज्य-भाजपा ने इसाई समुदाय को लुभाने के प्रयास बढ़ावा दिए हैं। जहां तक साई समुदाय की वर्तमान

स्थिति का सवाल है उसे विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय रपटों और धार्मिक स्वतंत्रता सूचकांकों से समझा जा सकता है। शब्दान्तर न तोड़ो अभियानश के अनुसार, देश में हर दिन ईसाईयों की प्रताङ्गना की दो घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में....करीब 100 पास्टर और आम पुरुष और महिलाएं भी गैर-कानूनी अपरिवर्तन करवाने के आरोप में जेलों में बंद हैं, जबकि वे यात्रा जन्मदिन मना रहे थे या इतवार की विशेष प्रार्थना समाप्त कर रहे थे। एक ज्ञापन के अनुसार, सरकार कार्डिनलों और पास्टरों के खिलाफ अपनी विभिन्न जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर रही है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार, सन् 2022 के पहले साल महीनों में ईसाईयों पर हमलों की 302 घटनाएं हुईं। इनमें सॉलिडरिटी फोरम एंड इवैंजेलिकल फैलोशिप ऑफ इंडिया के आर्चविशप पीटर मेकेडो द्वारा दायर एक याचिकों के मुताबिक, शराज्य ऐसे समूहों के खिलाफ त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने में असफल रहा है जिन्होंने ईराई समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा की, नफरत फैलाने वाले भाषण दिए, उनके आराधना स्थलों पर हमले किये और उनकी प्रार्थना समाजों में व्यवहान उत्पन्न किये। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआई आरएफ) ने लगातार बौद्ध साल भारत को

विशेष सरोकार वाला देश निरुपित किया है और अमेरिकी सरकार से कहा है कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाए। ओपन डोर्स के अनुसार, वर्तमान सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के बाद से ईसाईयों पर दबाव में नाटकीय वृद्धि हुई है—हिन्दू अतिवादी अन्य धर्मों के लोगों पर बिना किसी भय के हमले करते हैं और कुछ इलाकों में उन्होंने गंभीर हिस्सा की है...बड़ी संख्या में राज्य सरकारें धर्मातिरण—विरोधी कानून लागू कर रही हैं जिनका घोषित उद्देश्य हिन्दुओं का जबरदस्ती दूसरे धर्मों में परिवर्तन रोकना है मगर असल में उनके बहाने ईसाईयों को धरमकाया और प्राड़ित किया जाता है...पास्टर होना इस देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाला काम बन गया है। हिन्दू अतिवादी पास्टरों पर हिंसक हमले रहे हैं ताकि आम ईसाईयों के मन में डर का भाव बैठाया जा सके। ईसाई समुदाय की वर्तमान स्थिति की जड़ में है हिन्दू राष्ट्रवादी आत्मान जिसमें इस्लाम और ईसाईयत को विदेशी धर्म माना जाता है। आरएसएस के द्वितीय सरसंघाचालक एम.एस.स. गोलवलकर ने अपनी पुस्तक शब्द औफ थोट्स में लिखा है कि ईसाई और कम्युनिट, हिन्दू राष्ट्र के आंतरिक शरू हुए। आरएसएस की शाखाओं में भी इसी आशय की बातें सिखाई जाती हैं। हिन्दू राष्ट्रवादी गतिविधियों में जश्शल के साथ ईसाईयों के खिलाफ हिंसा सबसे पहले देश के आदिवासी इलाकों में शुरू हुई। प्रचार यह किया गया है कि ईसाई मिशनरीज जबरियां गोखाड़ी और लोभ—लालच आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं। ईसाई धर्म भारत के सभी देशों पुराने धर्मों में से एक है। ऐसे कहा जाता है कि सेंट थोमस मालाबार के तट पर उत्तरे 3500 52 ईर्षी में उन्होंने वहां देश पहले वर्च की स्थापना की। वह अन्य स्रोतों के अनुसार, वे चौथे सदी में मालाबार आये थे। चौथे सदी 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में ईसाईयों का प्रतिशत 2.3 है। मजे बात यह है कि सन 1971 ईसमें लगातार गिरावट आ रही है रु 1971—2.60फीसदी 1981—2.44फीसदी, 1991—34फीसदी, 2001—2.30फीसदी 2011—2.30फीसदी (सभी आधिकारिक जनगणना से)। मगर बैसिक रेट के दुधधारा के नवीजे में गुजरात के डांग में सबसे पहले (1998) दिसंबर 1998 से लेकर जनवरी 1999 (तक) ईसाई—विदेशी हिंसा हुई। इसके बाद, जनवरी 1999 की रात आरएसएस के अनुषांगिक संगठन बजरंग दल कार्य करता राजे द्रव्य पर उर्फदारासिंह ने पास्टर ग्राम स्टेस और उनके दो मासूम पुत्रों को जिंदा जला दिया। दारामाद इस समय उप्रकैद की साथ काट रहा है। इस घटना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ केशव नारायणन ने दूनिया के काट

हले में यादा, १६ से रही वसे तासा नस और के छुच्छी थोकी सन् गार, रियों की से रही दी, २-१२ तत के लगवाल मनुव्रों सेहं जा को भार लाले कारनामों की सूची का हिस्सा बताया। रेंट्स ऑस्ट्रलियाई मिशनरी थे और ओडिशा के क्योंज़गर, मनोहरपुर में काम करते थे। जब वे अपने दो बच्चों टिमोथी और फिलिप के साथ एक खुली जीप में सो रहे थे तब दारासिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर तीनों को जिंदा जला दिया। आरोप यह लगाया कि कुछ रोगियों की सेवा के बहाने वे ६ पर्मपरिवर्तन करवा रहे थे। घटना की जांच के लिए नियुक्त वाधवा आयोग ने पाया कि पास्टर रेंट्स धर्मपरिवर्तन में संलग्न नहीं थे और जिस इलाके में वे काम कर रहे थे वह की ईसाई आवादी में कोई बदोत्तरी नहीं हुई थी। इसके बाद से दूरदराज के इलाकों में ईसाई—विरोधी हिंसा जारी रही। अधिकांश मामलों में इस तरह की हिंसा क्रिसमस के आसपास होती थी। फिर २५ अगस्त, २००८ को ओडिशा के कंधमाल में भयावह हिंसा शुरू हुई जिसमें १०० से ज्यादा ईसाई मारे गए। ईसाई महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली बलाकार की घटनाएं हुईं और कई बच्चों को आग के हवाले कर दिया गया। तब से ईसाई—विरोधी हिंसा चल ही रही है यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस पर ज्यादा शोरशराबा न हो। अक्सर दूरदराज के इलाकों में काम रहे पारियों को तब धेरा जाता है जब वे प्रेयर मीटिंग संचालित कर रहे हों। बजरंग दल और उसके जैसे अन्य संगठनों के सदस्य प्रेयर मीटिंग्स में बाधा डालते हैं। पारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उहें परेशन किया जाता है। मणिपुर में ईसाईयों के खिलाफ करीब सात महीनों से हिंसा चल रही थी। कुकी, जिनमें से अदिकांश ईसाई हैं, डबल इंजन सरकार के निशाने पर हैं। मणिपुर और दिल्ली दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस ईसाई—विरोधी हिंसा को रोकना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। वे दुनिया भर में जा रहे हैं मगर मणिपुर के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कुछ हिम्मतवर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस इलाके में भ्रमण कर हिंसा की आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते इस खाई को भरना मुश्किल होगा। इस प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, वह केवल छाव बनाने की कायदह है। करत में कई ६ नीं ईसाई इस हिन्दू बहुसंख्यकवादी राजसीति के जाल में फंस रहे हैं। यह भी सच है कि ईडी, इनकम टैक्स आदि के कहर से बचने के लिए ईसाई समुदाय के शीर्ष धर्मिक नेतृत्व का एक हिंसा सरकार के साथ खड़ा होने को आतुर है। हमें यह समझाना होगा कि मोदी एंड कंपनी एक तरफ तो ईसाई समुदाय को हाशिये पर धकेल देना चाहते हैं तो दूसरी ओर वे चुनावों में उनके बोट भी हासिल करना चाहते हैं।

हटाने के लिए मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की राजनीतिक गतिविधियों के पीछे उन्हीं का हाथ माना जाता है। लेकिन अपने रुख में पूर्ण बदलाव के बाद जमील अब यामीन के प्रमुख पक्षकार बन गये हैं और पीपुल्स नेशनल फ्रंट (पीएनएफ) नामक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के प्रयासों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। चुनावी जीत के जश्न के कार्यक्रम में यामीन की उपस्थिति की अनुमति देने में डॉ. मुझज्जू ने की ओर से दिखायी गयी उपेक्षा के बारे में जमील ने कहा, ‘वेशक हमें उम्मीद थी कि वे इस दोस्ती और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का सम्मान करना जारी रखेंगे। यामीन भी इसके उतने ही हकदार हैं। समारोह के दौरान उन्हें उचित श्रेय और धन्यवाद मिलाना चाहिए था। लेकिन हमने इस संबंध में कुछ भी नहीं सुना और इस बात ने तुरंत भावनामुक रूप से हम पर गहरा प्रभाव डाला। यह भी बताया जाता है कि चुनाव में जीत के बाद मुझज्जू ने जब विजयी संघीणन दिया तो उसके दीक बाद उन्हें यामीन का फौज आया। लेकिन मुझज्जू ने कॉल का जवाब देने से ही ढंकार कर दिया। यही नहीं, मुझज्जू ने यामीन के शकौल में बैकूच सदेशों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पट्टना में भव्य अभिनंदन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया है। नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास कर उनके जीवन को सहज, सरल बनाने के साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता उन महापुरुषों के योगदान से नई पीड़ी को अवगत करवाने का कार्यी भी करना है, जिससे भारतीय समाज को संस्कार मिले। भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण के प्रसंगों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पहल के साथ ही नई शिक्षा नीति में सनातन संस्कृति का पाठ्यक्रमों में समावेश हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने सांवीधनी आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी। मध्यप्रदेश में जहाँ-जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पटना में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शंख ध्वनि के बीच दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुण्याच्छ, शॉल व अभिनंदन पत्र भेंट कर तथा मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र प्रसाद, महासचिव (पूर्व आईएप्स) डॉ. गोरेताल यादव, महामंडलेर भर्महंत डॉ. सुखेंद्र दास, विहार प्रदेश यादव महामध्यम, श्री कृष्ण चेतना परिषद् श्री कृष्ण चेतना संघ, श्री कृष्ण विचार मंच श्री गोपीकृष्ण गो आश्रम, जयपाल सिंह यादव, फाउंडेशन के पदाधिकारियों आदि ने स्वागत किया। भगवान् श्री कृष्ण की शिक्षा-दीक्षा हुई उज्जैन में, उनका जीवन धर्म की स्थापना में बीतामुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता सीता की जन्मस्थली विहार आकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ ऐसी परिव्रत धर्ती को मैं प्रणाम करता हूँ। यह भगवान् महावीर स्वामी जी की धरती है, जिससे विहार की पहचान है। साथ ही स्मार्त अशोक की भी धरती है। स्मार्त अशोक का मध्यप्रदेश उज्जैन से खासतौर पर अलग तरह का रिश्ता रहा है हजारों साल से मध्यप्रदेश और विहार का रिश्ता है। प्राचीन काल से मध्यप्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की नरर्म में ही भगवान् श्री कृष्ण का विवाह हुआ भगवान् श्री कृष्ण की शिक्षा-दीक्षा भी उज्जैन में हुई। शिक्षा के मामले में हमारा समाज

कितना जागृत है, इसका उदाहरण पांच हजार साल पहले भगवान् श्री कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान् श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो ऐसा उदाहरण दुनिया में अद्भुत

पवित्रतम ग्रन्थों में शामिल है। गीता आज भी सबका मार्ग दर्शन करती है। कोई भी क्रान्तिकारी हो, आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी, तो उसका जीवन अधरा है।



जीवन के किसी मार्ग पर जिसने भी बड़ा संकल्प लिया गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब भगवान् श्री कृष्ण को हमरे वंश का तो मानते ही हैं, लेकिन भगवान् श्री कृष्ण की पहचान किसीने है पूरे समाज के अंदर जहाँ कई अव्यवस्थाएँ दिखे, जहाँ कई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़का अधर्म के खिलाफ़

संघर्ष करने का कदम उठाया तो वह केवल
एकमेव भगवान् श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने
पूरे जीवन को धर्म की स्थापना के लिए
खपाया।

अमेरिका, इंग्लैण्ड में भी गाय माता बहुत सरे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में काफी अंतर है। हम अशक्त और बीमार गायों की देखभाल भी करते हैं। उनके हाल पर नहीं छोड़ देते। हम गाय माता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का बास देखते हैं। गायों में माँ का स्वरूप भी देखते हैं। गौ-माता का वास्तविक सम्मान हमारे देश की संस्कृति है।

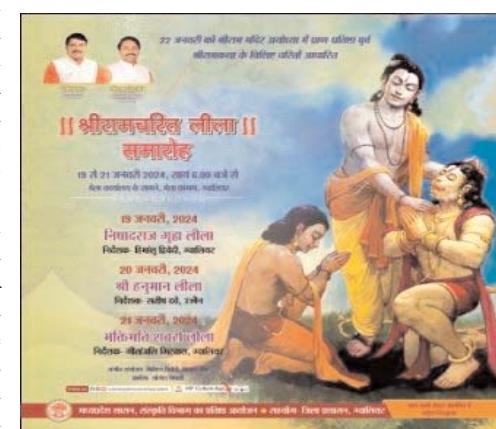
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान् श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ है। माँ यशोदा ने उन्हें पाल-पोस कर बड़ा किया। वह बालक न कभी डरता है और न भयभीत होता है। दुनिया की चुनौती का सामना करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जो भी आज भी हमें रोमांचित और गर्व से भर देता है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था यह ऐसे ही पैदा नहीं होती, इस आस्था, भक्ति, श्रद्धा पैदा करने के लिए समूचे जीवन को एक तरह से दुनिया के समने प्रदर्शित करने की जिनकी आध्यात्मिक चेतना जीवन भर काम आती है, ऐसे गोपाल कृष्ण की जय-जय कार महसूस कर सकते हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का श्री कृष्ण चेतना विचार मंच द्वारा स्वागत किया गया। कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्लेह, समाज और आत्मीयता से डॉ. यादव का स्वागत किया।

एनएचएआई की कमाई बेहतर, लेकिन शिवपुरी से गुना तक का हाइवे राम भरोसे



जिम्मेदारी है कि वह पूरी सड़क को सही करे। आगरा से मुंबई तथा भोपाल की ओर जाने वालों एक मात्र शिवपुरी गुना हाथवे दिन रात चलत है इस पर सबसे ज्यादा वाहनों का लोड है लकिन टोल कंपनी अपना मुनाफा तो देख रही है उसे वाहन चालकों और उस पर सवार यात्रियों की सुविधाओं का बिलकुल भी ख्याल नहीं है। न ही कंपनी द्वारा ठास कार्रवाई कर पूरी सड़क को ठीक कराया जा रहा है हां एक दो जगह पैच रियेकर करकर सड़क को दुरुस्त करा दिया गया है वाकी पूरी सड़क ऐसे ही आंखु बहा रही है। टोल कंपनी के अधिकारी भी कहने पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वह तो फास्ट टेक से पैसे काटकर सरकार की जेबें भरने पर लगे हैं जबकि सड़क को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी टोल कंपनी की है। इस सड़क पर बस चालक कार चालक खासे परेशानी से सफर पूरा करते हैं। अब देखना है यह राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक यूं ही यात्रियों के लिए दुविधा का कारण बना रहेगा इसका इंतजार रहेगा।

ग्वालियर में 19 से 21 जनवरी तक होगा श्रीरामचरित लीला समारोह का आयोजन



इन तिथियों में हर दिन समावंकल 6 बजे से विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाएगा। श्रीरामचरित लीला समारोह के अंतर्गत 19 जनवरी को हिमांशु द्विवेदी के निर्देशन में +निषादराज गुहा लीला+ का मंचन होगा। इसी तरह 20 जनवरी को सतीश दत्त उज्जैन द्वारा निर्देशित +श्री हनुमान लीला+ का मंचन किया जाएगा। लीला समारोह के तहत 21 जनवरी को सुश्री गीतांजलि गिरवाल के निर्देशन में +भक्तिमति शबरी लीला+ का मंचन किया जायेगा।

हाईरिस्टिक शृंखला की महिलाओं के वोटरकार्ड, आधारकार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से लाभान्वित करने लगाया गया शिविर



ग्वालियर 7 मध्यप्रदेश राज्य एडस नियंत्रण समिति के माध्यम से आदर्श समाज सेवा शिक्षा समिति द्वारा हाई रिस्क रुप की महिलाओं के बोटरकार्ड, आधारकार्ड तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु समृद्धायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन आयोग श्रीमती विनीता जैन तथा अच्छक्ष के रूप में उन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं के पांडेय और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विधिक अधिकारी दीपक शर्मा, बेटी है तो कल है संस्था की श्रीमती वंदना भूषण प्रेमी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की मुख्यता श्रीमती विनीता जैन ने इस अवसर पर कहा कि हाई रिस्क रुप की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा से जो? ना सासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में आदर्श समाज सेवा शिक्षा समिति कई वर्षों से सराहनीय कार्य कर रही है। समुदाय की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना से जो?ने का एक नेक कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में परियोजना प्रबंधक परवन कुमार नरवरिया द्वारा एचआईझी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में बड़ी सख्ती में महिलाओं के बोटरकार्ड, आधारकार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के मंत्रिश्वर में लाभान्वित किया गया।

राम मंदिर के साथ भाजपा चुनावी
मोड़ में, कभी भी हो सकते हैं चुनाव

भोपाल। केन्द्र सरकार राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद पूरा तरह से चुनावी मोड में आ सकती है। राम मंदिर के कार्य के साथ ही फरवरी में आम चुनावों की अनुशंसा कर सकती है। इसके बाद निर्वाचन आयोग माचया या अप्रैल में कभी भी चुनावों की तिथियों का ऐलान कर सकता है। स्ट्रोंग के मुताबिक केन्द्र के सभी मंत्रियों व सत्तारूप? भाजपा के सभी संसदीयों के भी भाजपा आलाकमान ने इशारा कर दिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहे और कार्यकर्ताओं व आम जनता से संपर्क में र्हे रहे। कुल मिलाकर मोदी सरकार अपने काम के बदले अब फिर जनता के बीच आम चुनावों के माध्यम से जाने की तैयारी कर रही है। इस बास सरकार के मुखिया सहित पार्टी मुखिया व आलाकमान ने 400 पार सीटों का लक्ष्य सामने रखा है। वैसे भी राममंदिर का कार्य पूरा होने से भाजपा के हासिले बल्कं है और कार्यकर्ता भी चुनावी रण के लिये तैयार हैं।



भोपाल को स्पोर्ट्स टूरिज्म हब बनाया जायेगा :खेल मंत्री



भोपाल । खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि भोपाल को स्पोर्ट्स टूरीज़ का हब बनाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने आज राज्य शूरिंग अकादमी का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद उन्होंने नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानकारी भी ली। मंत्री सारंग ने टूरीज़ विभाग के साथ कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने उच्च शिक्षा, खेल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग से समर्पण कर खेल में एक साथ प्रतिभाओं को तराशें को कहा। मंत्री सारंग ने खेल गतिविधियों के लिये नये स्थान चयनित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि युवाओं को शहर के विभिन्न स्थानों पर खेल गतिविधियों से जोड़े के लिये भी कार्य किया जाना होगा। मंत्री सारंग ने फायर रेंज, 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर रेंज के साथ शॉटिंग रेंज का अवलोकन किया। उन्होंने प्रत्येक रेंज पर खिलाड़ियों से बात कर उनका उत्तराहवधन किया। सारंग ने प्रशिक्षकों से खिलाड़ियों की प्रगति के बारे में जान और खेल प्रतिभा में निवार के लिये यथासंभव सुविधाएं उत्तरव्य कराने का आश्रित दिया। मंत्री सारंग ने भी 10 मीटर और शॉटिंग रेंज पर निशान साधा स्पर्धित भारतीय गयफल संघ राजीव भट्टिया ने बताया कि वर्तमान में राज्य शूरिंग अकादमी में 8 से 22 जनवरी तक गयफल, पिस्लल झीड़िया वी टीम के ग्रीष्मीय ट्रॉयल चल रहे हैं। कोलेज डिजाइनर्स ऑफिटेक्ट संजय यादव ने नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की प्रगति की जानकारी दी। निर्णीकरण के

दैरान अपर मुख्य सचिव सुमी सिंहा भाद्राज, संचालक रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक बी.एस. यादव, शूटिंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक अनुरुण अवासी जयंतीप्रकाश और पी.एन. प्रकाश के साथ अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी, ग्राम गोरा में 37 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी में देश की सभीसे अच्छी शूटिंग खेल की सुविधा राज्य शासन ने निर्मित की है। शूटिंग अकादमी भोपाल में 10 मीटर की 70 लेन, 25 मीटर की 50 लेन और 50 मीटर की 60 लेन की अत्याधिक शूटिंग रेंज बनाई गई है। कैम्पस में शॉटान की भी विश्व-स्तरीय 5 रेंज निर्मित की गई हैं। इनमें 3 पर्सनल-तैयार और 2 प्राप्तिरत हैं।